



## भारत में संस्थागत एवं नवीन बैंकिंग व्यवस्था : एक तुलनात्मक विश्लेषण

डॉ. खेमचन्द गुर्जर

व्याख्याता

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग

एस.एन.के.पी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमकाथाना (राजस्थान)

### सार

भारत में बैंकिंग प्रणाली का इतिहास काफी समृद्ध और पुराना है। यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करती है, जो समय के साथ पारंपरिक स्वरूप से विकसित होकर एक आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। भारतीय बैंकिंग को मोटे तौर पर संस्थागत बैंकिंग और नवीन बैंकिंग व्यवस्था (डिजिटल और फिनटेक आधारित) के रूप में समझा जा सकता है। संस्थागत बैंकिंग से तात्पर्य देश में स्थापित, विनियमित और पारंपरिक बैंकिंग संरचना से है, जिसका विकास ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद के राष्ट्रीयकरण के दौर तक हुआ है। आधुनिक संस्थागत बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज में प्रेसिडेंसी बैंकों (बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, और मद्रास) की स्थापना के साथ हुई, जिनका विलय बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (1921) में कर दिया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1935 में देश के केंद्रीय बैंक के रूप में हुई, जो सम्पूर्ण बैंकिंग और मौद्रिक नीति का विनियमन करता है। 1969 और 1980 में प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में संस्थागत बैंकिंग की संरचना में मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), सहकारी बैंक और विकास वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

### मुख्य शब्द

बैंकिंग, प्रणाली, वित्तीय, मौद्रिक

### प्रस्तावना

संस्थागत बैंक जमा स्वीकार करने, ऋण प्रदान करने, और भुगतान प्रणाली को सुचारू बनाने जैसे पारंपरिक कार्य करते हैं, जो आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भी इनकी शाखाओं और व्यवसाय प्रतिनिधियों के विशाल नेटवर्क का बड़ा योगदान रहा है।

नवीन बैंकिंग से आशय वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और डिजिटलीकरण द्वारा संचालित आधुनिक बैंकिंग सेवाओं से है। इसने पारंपरिक बैंकिंग के दायरे और गति को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है।

#### 1. प्रमुख घटक और नवाचार

डिजिटल भुगतान प्रणाली: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की सबसे बड़ी नवीन सफलता है, जिसने वास्तविक समय में भुगतान को अत्यधिक सरल बना दिया है।

भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक : ये नए संस्थान विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं (जैसे छोटे ऋण, जमा और भुगतान सेवाएँ) को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिससे वित्तीय पहुंच का विस्तार हुआ है।



नियोबैंक : ये वे डिजिटल बैंक हैं जिनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती। वे पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी में काम करते हैं और अपने ग्राहकों को पूरी तरह से ऑनलाइन (ऐप-आधारित) और लागत प्रभावी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ : देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि बैंकिंग सेवाएँ डिजिटली सुलभ हों, खासकर ऐसे लोगों के लिए जिनके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बुनियादी ढाँचा नहीं है।

नवीन बैंकिंग ने सुविधा, गति और पारदर्शिता को बढ़ाया है। इसने बैंकिंग सेवाओं को 'शाखा-केंद्रित' से 'ग्राहक-केंद्रित' और 'एनीटाइम-एनीवेयर' मॉडल में बदल दिया है। यह युवा, तकनीकी-सक्षम और सुविधा-उन्मुख ग्राहकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है, और इसने वित्तीय समावेशन को अगले स्तर तक पहुँचाया है।

भारतीय बैंकिंग का भविष्य संस्थागत और नवीन व्यवस्थाओं के सफल सह-अस्तित्व और समन्वय में निहित है।

मजबूत नींव: संस्थागत बैंक पूंजी, विश्वास और नियामक ढाँचे की मजबूत नींव प्रदान करते हैं।

तकनीकी उन्नयन: पारंपरिक बैंक भी अपनी सेवाओं को डिजिटलाइज़ कर रहे हैं, जिससे उनकी शाखा-आधारित पहुँच और डिजिटल क्षमताओं का मेल हो रहा है।

चुनौतियाँ: हालांकि, नियामक अनुपालन, साइबर सुरक्षा, और ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी इस समन्वय की राह में प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

भारत की संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था ने देश की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखा है, जबकि नवीन बैंकिंग ने उसे गति, दक्षता और व्यापकता प्रदान की है। यह गतिशील विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की सफलता और स्थिरता उसकी वित्तीय प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करती है। इस वित्तीय प्रणाली के केंद्र में संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था स्थित है, जिसे प्रायः अर्थव्यवस्था की "सुदृढ़ नींव" या "रीढ़ की हड्डी" कहा जाता है। संस्थागत बैंकिंग का अर्थ केवल धन के लेन-देन से नहीं है, बल्कि यह औपचारिक रूप से स्थापित, नियामक निकायों द्वारा नियंत्रित और कानूनी ढाँचे के भीतर संचालित होने वाली बैंकों की संपूर्ण प्रणाली को दर्शाता है। यह वह ढाँचा है जो लोगों के विश्वास और पूंजी के कुशल प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे सतत आर्थिक विकास संभव हो पाता है।

### साहित्य की समीक्षा

भविष्य में, नवीन बैंकिंग व्यवस्था और अधिक व्यक्तिगत और सहज होने की ओर अग्रसर है। ओपन बैंकिंग, जहाँ ग्राहक अपनी सहमति से तीसरे पक्ष के ऐप्स के साथ डेटा साझा कर सकते हैं, से वित्तीय उत्पादों में और अधिक नवाचार आने की उम्मीद है। ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियाँ पारदर्शिता और सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जा सकती हैं। [1]

नवीन बैंकिंग व्यवस्था केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक आर्थिक परिवर्तन है। डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग को एक उत्पाद से बदलकर एक सहज अनुभव बना दिया है। यदि सुरक्षा और समावेशन



की चुनौतियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जाता है, तो यह युग न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने और आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता रखता है। [2]

आधुनिक युग में तकनीक ने हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और बैंकिंग भी इससे अछूती नहीं रही है। नवीन बैंकिंग व्यवस्था पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़कर डिजिटल और तकनीक आधारित सेवाओं पर केंद्रित है। भारत में डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग सेवाओं को तेज़, सुरक्षित और अधिक समावेशी बना दिया है। [3]

भारत में संस्थागत एवं नवीन बैंकिंग व्यवस्था : एक तुलनात्मक विश्लेषण

संस्थागत बैंक दो प्राथमिक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं: वित्तीय मध्यस्थता और पूंजी निर्माण। सबसे पहले, वे आम जनता और व्यवसायों से बचत (जमा) स्वीकार करते हैं, उन छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा करके एक बड़ी पूंजी में परिवर्तित करते हैं। दूसरा, वे इसी पूंजी को उत्पादक निवेशों (जैसे कि उद्योगों को ऋण, कृषि ऋण और आवास ऋण) के रूप में जरूरतमंदों तक पहुँचाते हैं। यह प्रक्रिया संसाधनों के निष्क्रिय पड़े रहने के बजाय उन्हें गतिशीलता प्रदान करती है। एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था तरलता बनाए रखती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों का चक्र बिना रुके चलता रहता है।

तुलनात्मक विश्लेषण: मुख्य अंतर

आधार	संस्थागत बैंकिंग (पारंपरिक)	नवीन बैंकिंग (डिजिटल/नियोबैंक)
उपस्थिति	भौतिक शाखाओं का व्यापक नेटवर्क	पूरी तरह से ऑनलाइन/डिजिटल; कोई भौतिक शाखा नहीं
संचालन लागत	उच्च (भौतिक बुनियादी ढांचे के कारण)	कम (प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल के कारण)
पहुँच	मुख्य रूप से बैंक के कामकाजी घंटों के दौरान	24x7 उपलब्ध, कहीं से भी
ग्राहक ऑनबोर्डिंग	जटिल और समय लेने वाली	सरल और त्वरित (आमतौर पर पूरी तरह से डिजिटल)
विश्वास/सुरक्षा	उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता (लंबा इतिहास)	नवाचार में तेज, लेकिन सुरक्षा को लेकर अधिक संवेदनशील
नवाचार	धीमी गति से डिजिटल परिवर्तन को अपनाना	नवाचार पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित

संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति इसकी विश्वसनीयता और पारदर्शिता में निहित है। ये बैंक केंद्रीय बैंक जैसे कठोर नियामक संस्थाओं के दायरे में काम करते हैं। ये नियामक कड़े नियम (जैसे पूंजी पर्याप्तता



अनुपात, जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश) लागू करते हैं, जो बैंकों को अत्यधिक जोखिम लेने से रोकते हैं और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह विनियमन आम जनता में विश्वास पैदा करता है, जो उन्हें निर्भीक होकर अपना पैसा बैंक में जमा करने के लिए प्रेरित करता है। यह संस्थागत नियंत्रण ही वित्तीय संकट के समय प्रणाली को टूटने से बचाता है, जिससे यह वास्तव में एक मज़बूत नींव बन जाती है।

संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। जन धन योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, जिससे दूर-दराज के और कम आय वाले लोगों को भी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच मिलती है। यह किसानों, छोटे उद्यमियों और आम नागरिकों को ऋण, बीमा और निवेश जैसी सुविधाएँ प्रदान करके गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, संस्थागत बैंकिंग एक समावेशी और न्यायसंगत विकास पथ का समर्थन करती है।

संस्थागत बैंकिंग व्यवस्था किसी भी राष्ट्र के आर्थिक परिदृश्य के लिए एक अपरिहार्य और सुदृढ़ नींव है। यह न केवल पूंजी को गतिशील बनाती है और वित्तीय मध्यस्थता सुनिश्चित करती है, बल्कि सख्त विनियमन के माध्यम से स्थिरता और सार्वजनिक विश्वास भी स्थापित करती है। एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के बिना, कोई भी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश, सतत विकास या संकटों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकती है। इसलिए, इस व्यवस्था को लगातार मजबूत और आधुनिक बनाना राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बीसवीं सदी के अंत और इक्कीसवीं सदी की शुरुआत ने एक ऐसे युग का सूत्रपात किया है, जहाँ वित्तीय लेन-देन अब कागज़ और काउंटर तक सीमित नहीं रहे। इसे नवीन बैंकिंग व्यवस्था या 'डिजिटल बैंकिंग क्रांति' का युग कहा जा रहा है। यह क्रांति सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संगम से संभव हुई है, जिसने पारंपरिक बैंकिंग मॉडल की सीमाओं को तोड़कर ग्राहकों को अभूतपूर्व सुविधा, गति और पारदर्शिता प्रदान की है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक, हर समय और न्यूनतम लागत पर पहुँचाना है।

नवीन बैंकिंग व्यवस्था की रीढ़ डिजिटल तकनीक है। मोबाइल बैंकिंग ऐप्स ने बैंकों को सीधे ग्राहकों की जेब में पहुँचा दिया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे त्वरित भुगतान प्रणालियों ने भारत सहित कई देशों में लेन-देन की गति को बदलकर रख दिया है, जिससे न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि छोटे व्यवसायों के लिए भी भुगतान तत्काल और सरल हो गया है।

इंटरनेट बैंकिंग और चौबीसों घंटे उपलब्ध सेवाएं अब ग्राहकों को बैंक शाखा के समय का इंतजार किए बिना फंड ट्रांसफर करने, बिलों का भुगतान करने और निवेश करने की स्वतंत्रता देती हैं। इसके अलावा, रोबो-सलाहकार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्राहक सेवा तथा व्यक्तिगत वित्तीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डिजिटल बैंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय समावेशन पर पड़ा है। दूर-दराज के क्षेत्रों में जहाँ बैंक शाखाएँ खोलना संभव नहीं था, अब मोबाइल फोन के माध्यम से बुनियादी बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हैं। इससे अर्थव्यवस्था के उन वर्गों को औपचारिक वित्तीय तंत्र में शामिल होने का अवसर मिला है जो पहले इससे वंचित थे।



व्यवसाय के दृष्टिकोण से, डिजिटल समाधानों ने परिचालन लागत में कमी लाई है और दक्षता में वृद्धि की है। शाखाओं पर निर्भरता कम होने से बैंकों के संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहे हैं, जिसका लाभ अंततः कम ब्याज दरों और बेहतर सेवाओं के रूप में ग्राहकों को मिलता है।

डिजिटल क्रांति के अपने खतरे भी हैं। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। जैसे-जैसे लेन-देन ऑनलाइन हो रहे हैं, डेटा चोरी और हैकिंग का खतरा बढ़ रहा है, जिसके लिए बैंकों और नियामकों को लगातार अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना पड़ रहा है। इसके अलावा, समाज के एक बड़े हिस्से, विशेषकर वृद्धों और ग्रामीण आबादी, में डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बाधा है, जिसके लिए व्यापक शिक्षा और सरल इंटरफ़ेस की आवश्यकता है।

भारत में नवीन बैंकिंग व्यवस्था डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। यह पारंपरिक बैंकिंग के लाभों को बनाए रखते हुए सेवाओं को तेज़, सुरक्षित और समावेशी बनाती है। भविष्य में तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से यह व्यवस्था और अधिक मजबूत और प्रभावी बन सकती है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने पिछले दो सौ वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है, जो औपनिवेशिक काल के संस्थागत (पारंपरिक) बैंकिंग से लेकर वर्तमान के नवीन (डिजिटल-केंद्रित) बैंकिंग युग तक फैला हुआ है। संस्थागत बैंकिंग एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जबकि नवीन बैंकिंग (विशेष रूप से नियोबैंक और डिजिटल पहल) नवाचार और दक्षता ला रहा है। इस निबंध में दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

भारत में संस्थागत बैंकिंग प्रणाली की जड़ें ब्रिटिश राज में हैं, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ में प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना से हुई। राष्ट्रीयकरण (1969 और 1980) ने इसे और मजबूत किया, जिसका उद्देश्य ऋण पहुंच सुनिश्चित करना और कृषि तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था।

नवीन बैंकिंग व्यवस्था मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी-संचालित है, जिसका विकास 21वीं सदी में फिनटेक नवाचारों और बदलती ग्राहक अपेक्षाओं के कारण हुआ है। इसमें मुख्य रूप से नियोबैंक, भुगतान बैंक और पारंपरिक बैंकों द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहलें शामिल हैं। नियोबैंक पूरी तरह से डिजिटल होते हैं और उनकी कोई भौतिक शाखा नहीं होती है।

## निष्कर्ष

भारत में संस्थागत और नवीन बैंकिंग व्यवस्थाएँ एक-दूसरे की प्रतिद्वंद्वी होने के बजाय पूरक की भूमिका निभा रही हैं। संस्थागत बैंकों की विश्वसनीयता, मजबूत नियामक अनुपालन और व्यापक पहुँच ग्रामीण और पारंपरिक बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए अपरिहार्य है। वहीं, नवीन बैंकिंग दक्षता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रितता लाकर बाजार को बाधित कर रहा है। भविष्य की बैंकिंग प्रणाली वह होगी जो पारंपरिक बैंकों की स्थिरता और विश्वसनीयता को नवीन बैंकों की डिजिटल दक्षता और उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव के साथ एकीकृत करती है। भारत का बैंकिंग क्षेत्र इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ पारंपरिक खिलाड़ी भी अपने डिजिटल पदचिह्न बढ़ा रहे हैं और ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो वित्तीय समावेशन को और मजबूत करेगा तथा भारत को \$30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में मदद कर सकता



है।

### संदर्भ

सरॉय, राजस; जैन, प्रेक्षा; अवस्थी, साक्षी; ढल, शरतचंद्र। "भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दक्षता पर डिजिटल भुगतान अपनाने का प्रभाव।" जर्नल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (2013)

कुमार, अभिजीत। "डिजिटल संक्रमण और दैनिक सेवाओं में भारतीय बैंक अपने वैश्विक समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।" बिज़नेस स्टैंडर्ड (23 अप्रैल 2015)

"सामाजिक और विकास बैंकिंग से डिजिटल वित्तीय समावेशन तक: भारत में बैंकिंग का सफ़र" वैश्विक विकास और प्रौद्योगिकी पर परिप्रेक्ष्य, खंड 19, अंक 5-6 (2014)

"भारत में डिजिटल बैंकिंग: वित्त में क्रांति।" रुपीप (ब्लॉग), 2013

"डिजिटल बैंकिंग के 10 प्रमुख लाभ और यह बैंकिंग के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है।" इंडसइंड बैंक डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा में निजी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से आगे: आरबीआई रिपोर्ट।" द फाइनेंशियल एक्सप्रेस (30 जुलाई 2014)